16 मार्च, 2018

भारत-फिलिस्तीन सम्बंध: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुनर्आश्वासन दौरा

*डॉ. अतहर ज़फ़र**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 से 12 फरवरी 2018 तक चार अरब देशों - जॉर्डन, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) तथा ओमान के दौरे पर थे। इन वृहत्तर जलीय पड़ोसी देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बंधों को अधिक बेहतर बनाने की दिशा में यह दौरा काफी महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन होते हुए 10 फरवरी को फिलिस्तीन पहुंचे, क्योंकि फिलिस्तीन का बाहरी दुनिया से कोई सीधा हवाई सम्पर्क नहीं है। जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामल्ला जाने के लिए अपना निजी हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराया। यह एक ऐतिहासिक मौका था क्योंकि, ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला फिलिस्तीन दौरा था। वहां भारतीय प्रतिनिधिमंडल का 'शानदार' स्वागत किया गया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अलक़िलाद अल कुबरा (द ग्रैंड कॉलर) से सम्मानित किया।

हाल के वर्षों में भारत तथा फिलिस्तीन के बीच उच्च-स्तरीय राजनीतिक दौरों में वृद्धि हुई है। मई 2017 में राष्ट्रपति अब्बास पांचवीं बार भारत के दौरे पर आए। उनसे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जनवरी 2016 में फिलिस्तीन के दौरे पर गई थीं। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फिलिस्तीन के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे।

इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के बहुत जल्द शांतिपूर्ण तरीके से संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बनने की उम्मीद जताई। उन्होंने फिलिस्तीन की जनता का समर्थन करते हुए कहा कि, "फिलिस्तीन के लिए हमारा समर्थन दृढ़ तथा निरंतर है, जो हमेशा हमारी विदेश नीति में शीर्ष पर रहेगा। राष्ट्रपति अब्बास ने उन्हें वहां चल रही शांति प्रक्रिया तथा हाल के घटनाक्रम से अवगत कराया।

इस दौरे पर फिलिस्तीनी जनता के हित में द्विपक्षीय सहयोग के अलग-अलग क्षेत्रों में करीब 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 6 समझौता-पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता-पत्र हैं-

1.बेथलेहम के बेत सहौर में भारत-फिलिस्तीन सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना

2. महिला सशक्तिकरण के लिए भारत-फिलिस्तीन केंद्र 'तुराथी' का निर्माण

3. रामल्ला में एक नये नेशनल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना

4. मुथाला अल शौहादा गांव में एक स्कूल का निर्माण

5. तुबासा प्रांत में स्कूल का निर्माण

6. अबू दीस में लड़कों के लिए जवाहर लाल नेहरू स्कूल का विस्तार

निश्चित तौर पर फिलिस्तीन के बढ़ते विकास के लिए प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान समेत सभी क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही अन्य देशों तथा बहुपक्षीय संगठनों से मजबूत सम्बंध भी आवश्यक हैं। फिलिस्तीन के विकास के लिए भारत, फिलिस्तीन की सरकार तथा वहां की जनता को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए निर्माण तथा संस्थागत क्षमता के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत शिक्षा तथा प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, परियोजना सहायता तथा बजटीय मदद समेत कई क्षेत्रों में सहयोग किये जा रहे हैं। भारत ने फिलिस्तीन में रोजगार कौशल बढ़ाने के लिए रामल्ला में प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की है। फिलिस्तीन में भविष्य के राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत, रामल्ला में एक कूटनीतिक संस्थान भी खोलेगा। भारत में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी छात्र पढ़ाई के लिए आ रहे हैं जिसे देखते हुए देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ा दी गई हैं। इनमें वित्त, प्रबंधन, ग्रामीण विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों के बीच सबसे अधिक जोर शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा रहा है। 2015 में राष्ट्रपति के दौरे के समय दोनों देशों के बीच जो छह समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए उनमें पांच समझौते शैक्षणिक संस्थानों के बीच हुए थे। भारत ने फिलीस्तीनी नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा बढ़ा दी है जिससे आर्थिक विकास के साथ दोनों तरफ के आम लोगों के बीच भी बेहतर सम्बंध बनने की आशा है।

भारत तथा फिलिस्तीन के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक सम्बंध अपेक्षाकृत कमजोर हैं (अनुमानित रूप से करीब 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और ये इजरायल के रास्ते होते हैं। फिलिस्तीन की जनता भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखती है और भारत के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सम्बंधों में मजबूती चाहती है। निश्चित रूप से कृषि सहित कई क्षेत्रों में संभावनाएं हैं। फिलिस्तीन उच्च गुणवत्ता वाले जैतून का तेल बनाने के लिए मशहूर है। साथ ही वहां खजूर और गिरि की पैदावार भी काफी है। भारत में बढ़ती आय तथा स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ने के साथ जैतून के तेल की खपत, विशेषकर खाना बनाने में बढ़ रही है। इस क्षेत्र में व्यापार की संभावना और बेहतर हो सकती है, क्योंकि जैतून के तेल पर फिलिस्तीन की राष्ट्रीय निर्यात नीति (2014-18) में भी अपने निर्यात बाजार के विस्तार की बात कही गई है। हालांकि, फिलिस्तीन में भारत से निवेश के लिए वहां शांति तथा स्थिरता का होना आवश्यक है।

जहां तक इज़रायल और फिलिस्तीन से भारत की नीतियों का सम्बंध है तो सिर्फ इन्हीं दो देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भारत 'डी-हाइफनेशन' की नीति पर चल रहा है। इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ-साथ भारत ने इज़रायल, सऊदी अरब तथा ईरान के साथ अपने सम्बंध मजबूत किए हैं एवं स्वतंत्र रूप से द्विपक्षीय सम्बंधों को आगे बढ़ा रहा है। इस क्षेत्र में अलग-अलग देशों के साथ भारत के पारस्परिक सम्बंध विशेष रूप से आगे बढ़ रहे हैं, पर किसी भी देश को दूसरे से अधिक वरीयता निश्चित तौर पर नहीं दी जा रही है।

अरब-इज़रायल विवाद हो या साम्प्रदायिक विषमता, देशों की विभिन्न पारस्परिक आवश्यकताओं को देखते हुए किसी भी पक्ष के साथ सम्बंधों के विकास में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इज़रायल के साथ भारत के सैन्य तथा सुरक्षा सम्बंध हैं, जबकि अरब देशों के साथ मजबूत आर्थिक सम्बंध हैं। अरब की खाड़ी भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा वहां रहनेवाले प्रवासी भारतीयों की ओर से भेजी जाने वाली रकम को देखते हुए भारत के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। दूसरी तरफ, ऊर्जा की आपूर्ति के साथ-साथ अफगानिस्तान, मध्य एशिया तथा यूरेशिया से जोड़ने की दृष्टि से ईरान भी महत्त्वपूर्ण देश है।

भारतीय कूटनीति बाहरी प्रभावों से मुक्त है तथा खाड़ी के क्षेत्र मे यह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इस मामले में दिसंबर 2017 में भारत का पक्ष एक बार फिर सामने आया, जब अमेरिका ने येरूशलम को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की पहल की। भारत ने येरूशलम को इज़रायल की राजधानी घोषित करने के अमेरिका के निर्णय का समर्थन नहीं किया। भारत समेत 125 देशों से भी अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया कि येरूशलम की स्थिति, चरित्र तथा जनसांख्यिकीय संरचना में किसी भी तरह के परिवर्तन का प्रयास अमान्य होगा।

भारत के नीतिगत विकल्प तथा निर्णय पूरी तरह राष्ट्रीय हित, यथार्थवाद एवं राष्ट्रीय लोकाचार (चरित्र) और अंतरराष्ट्रीय आम सहमति पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री मोदी का फिलिस्तीन दौरा तथा यासिर अराफात की समाधि पर उनकी श्रद्धांजलि इस बात का मजबूत संकेत है कि भारत इस क्षेत्र में उन देशों के साथ है, जो लंबे समय से भारत के मित्र हैं।

***

** डॉ. अतहर ज़फ़र, शोध अध्येता, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली।*

डिस्क्लेमर: उपरोक्त विचार शोध अध्येता के निजी विचार हैं तथा परिषद के विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते।